



सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,

सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र० (भारत)

Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक-581/कु०स०का०/सि०वि०वि०/2026,

दिनांक- 23-07-2026

सेवा में,

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय :- नशा मुक्त भारत अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र के क्रम में प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नशा मुक्त भारत अभियान पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 16-07-2026 से 15-08-2026 तक किया जाना है, और दिनांक 15 अगस्त, 2026 को पुरस्कार वितरण भी किया जाना है। इसी क्रम में आज दिनांक 23-07-2026 पत्र निर्गत के तिथि से अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

नशा मुक्त विषय से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भाषण प्रतियोगिता, पैदल मार्च/रैली, नाटक, नुक्कड़ नाटक आयोजन, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, व्याख्यान, सेमिनार/वेविनार, नशा मुक्ति के पक्ष में स्लोगन लिखने का अभियान, योग कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाना है। (संलग्न पत्र)

प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1659/26-1-2026/1795110 दिनांक 21-07-2026 के क्रम नार्को-कोआर्डिनेशन (NCORD) की दिनांक 09-01-2026 को आयोजित 9वीं शीर्ष बैठक में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती घटनाओं पर विचार-विमर्श किया गया, जिसकी अध्यक्षता मा० केन्द्रीय गृहमंत्री, श्री अमित शाहजी द्वारा की गयी, जिसमें नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के सभी विभागों को 2029 तक रोडमैप तैयार करना चाहिए और इसके कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए। उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 03 वर्षों में सभी सम्बन्धित हितधारकों को पूरे देश में नशीली दवाओं के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ना होगा और भारत को "नशा मुक्त भारत" बनाना होगा तथा देश के युवाओं को नशीली दवाओं से बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना होगा।

उपर्युक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के पत्र दिनांक 20 मार्च, 2026 के क्रम में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के तहत प्रदेश में 03 वर्षीय कार्ययोजना (वर्ष 2026 से 2029) को निम्नवत क्रियान्वित कराये जाने (छाया प्रति संलग्न) के निर्देश दिये गये हैं।

अतः समस्त सम्बन्धित को अवगत कराना है कि संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तददिनांकित से प्रारम्भ करते हुए कार्यक्रम की विडियोग्राफी व जियोटैगिंग फोटोग्राफी कराना सुनिश्चित करें, जिससे मांगे जाने पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक- यथोपरि।

पत्रांक- /तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संकायाध्यक्ष, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।


कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।



कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

समस्त राज्य विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में नशा मुक्त अभियान के लिए प्रस्तावित विविध कार्यक्रम

- प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नशा मुक्त भारत अभियान पखवाड़ा आयोजन दिनांक 25.07.2026 से 08.08.2026 तक किया जाना तथा 15 अगस्त, 2026 को पुरस्कार वितरण किया जाना प्रस्तावित।
- नशा मुक्त विषय से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन।
- विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर छात्रों द्वारा नशा मुक्ति के पक्ष में पाँच किलोमीटर पैदल मार्च/रेली (स्लोगन बोर्ड के साथ) का आयोजन किया जाना।
- विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा पूर्व में जिस तरह से 120 से 150 किलोमीटर साईकिल रेली का आयोजन किया गया था और एक दिन महाविद्यालय/तहसील/ब्लाक स्तर पर छात्रों द्वारा विविध कार्यक्रम यथा— नाटक, नुक्कड़ नाटक आयोजन, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण का आयोजन।
- नशा मुक्त विषय पर विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन/व्याख्यान का आयोजन।
- कुलपतिगण द्वारा पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करके नारकोटिक्स विभाग के पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में एक दिन का "नशा मुक्ति" विषय को लेकर सेमिनार अथवा वेबिनार का आयोजन।
- सभी छात्रों द्वारा निर्धारित समयावधि में एक साथ मिलकर नशा मुक्ति के पक्ष में स्लोगन लिखने का अभियान तथा नशा मुक्ति के लिए सामूहिक प्रतिज्ञा।
- योग कार्यक्रम एक सप्ताह/एक पखवाड़ा तक आयोजन।
- छात्रों द्वारा मंच पर नाटक प्रतियोगिता का आयोजन।
- शहरों या तहसील के जो भी प्रतिष्ठान उपलब्ध हो वहां पर छात्रों द्वारा जागरूकता सभा का आयोजन।
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नशा मुक्त परिसर बनाये जाने हेतु एक दिवसीय स्वच्छता अभियान का आयोजन।
- विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति अभियान की निगरानी तथा कार्यक्रम आयोजन हेतु समिति का गठन।
- नशा मुक्ति अभियान में डाक्यूमेंट्री/फिल्म दिखाया जाना।

प्रेषक,

अनुराग यादव,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- प्रमुख सचिव, उच्च/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 5- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 6- महानिदेशक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 8- पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नारकोटिक्स फोर्स, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 9- क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, महानगर, लखनऊ।
- 10- निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 12- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 13- राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 21-07-2026

विषय: एनकॉर्ड एवं नशा मुक्त भारत अभियान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक गृह मंत्रालय (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-III/1/22/NCORD/9thApex/2025/Pt.-2(3) दिनांक 18.05.2026 एवं संलग्न भारत सरकार के संयुक्त पत्र संख्या- DO No.28-1/2026-PACE-Part(1) दिनांक 20.03.2026 तथा संयुक्त पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र संख्या-D.O.No. 12-1/2020-DP-II दिनांक 22.04.2026 (छायाप्रति संलग्न सहित) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नार्को-कोआर्डिनेशन (NCORD) की दिनांक 09.01.2026 को आयोजित 9वीं शीर्ष बैठक में नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती घटनाओं पर विचार-विमर्श किया गया, जिसकी अध्यक्षता मा० केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाहजी द्वारा की गयी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के सभी विभागों को 2029 तक का रोडमैप तैयार करना चाहिए और इसके कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध समीक्षा तंत्र स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बल देकर कहा कि युवाओं का स्वास्थ्य, उनकी सोचने और कार्य करने की क्षमता और समाज में बढ़ता असंतोष, ये सभी इस समस्या से जुड़े हुए हैं। यह घोषणा की गई कि 31 मार्च, 2026 के सभी हितधारक विभाग मिलकर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ 03 साल का एक सामूहिक अभियान शुरू करेंगे, जिसमें नशीली दवाओं के खिलाफ सभी स्तंभों की कार्यप्रणाली को परिभाषित किया जाएगा, लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे और समयबद्ध समीक्षा की जाएगी। इसलिए NCORD की 9वीं शीर्ष बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 03 वर्षों में सभी संबंधित हितधारकों को पूरे देश में नशीली दवाओं के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ना होगा और भारत को "नशा मुक्त भारत" बनाना होगा तथा देश के युवाओं को नशीली दवाओं से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।

उपर्युक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 20 मार्च, 2026 के क्रम में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) के तहत प्रदेश में 03 वर्षीय कार्ययोजना (वर्ष 2026 से 2029) को निम्नवत् क्रियान्वित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं-

प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्त भारत अभियान की 03 वर्षीय कार्ययोजना (वर्ष 2026-2029)

क्र.स	क्या करना है?	कैसे करना है?	कौन करेगा?
1	विद्यालयों द्वारा स्वयं को तबाकू एवं नशा मुक्त घोषित करने हेतु समर्पित "नशा मुक्त विद्यालय" पोर्टल का शुभारंभ।	DoSEL द्वारा "नशा मुक्त विद्यालय" नामक एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से विद्यालयों में ड्रग-फ्री जोन/ तंबाकू-मुक्त शैक्षणिक संस्थान (ToFEI) के अनुपालन की निगरानी की जाएगी। UDISE+ में पंजीकृत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी विद्यालय इस पोर्टल पर अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।	DoSEL / प्रदेश के विद्यालय

2	सभी शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को "नशा-मुक्त क्षेत्र (Drug-Free Zone)" घोषित किया जाए।	9वीं NCORD बैठक में जारी निर्देशों के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को "ड्रग फ्री जोन" घोषित किया जायेगा। स्कूल के प्रवेश द्वार/निकास द्वार पर अनिवार्य रूप से एक साइनबोर्ड लगाया जायेगा, जिसपर लिखा होगा कि:- इस दायरे में किसी भी प्रकार के ड्रग्स की बिक्री एवं सेवन प्रतिबंधित है। उल्लंघन के मामले में इसकी रिपोर्ट पुलिस/नारकोटिक्स कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दी जायेगी।	विद्यालय/ स्थानीय पुलिस जिला नारकोटिक्स कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ / स्थानीय प्रशासन
3	मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम से संबंधित आयु-उपयुक्त पाठ्यक्रम को जीवन कौशल (Life Skills)/ स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल करना।	यह विषय पहले से ही NCERT के पाठ्यक्रम में मिडिल स्तर से तथा CBSE के लाइफ स्किल्स पाठ्यक्रम में सभी विद्यालयी स्तरों पर सम्मिलित है। अब राज्य शिक्षा बोर्डों से भी अनुरोध किया जाएगा कि वे इसे अपने पाठ्यक्रम में अनुकूलन (Adaptation) या अंगीकरण (Adoption) के माध्यम से शामिल करें।	DoSEL/ NCERT / राज्य
4	तंबाकू, नशीले पदार्थ एवं मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर मानकीकृत सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री का विकास।	छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए तंबाकू, नशीले पदार्थों तथा मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित मानकीकृत IEC सामग्री विकसित की जाएगी। इसमें पोस्टर, पुस्तिकाएँ (हैंडबुक), वृत्त चित्र (डॉक्यूमेंट्री) एवं फिल्में शामिल होंगी। यह सामग्री NCERT के सहयोग से तैयार की जाएगी तथा SCERTs के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद एवं स्थानीय संदर्भ के अनुसार अनुकूलन (Contextualization) किया जाएगा।	DoSEL/NCERT/राज्य/ SCERTs
5	शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, जिसमें नशीले पदार्थों के सेवन के जोखिम वाले बच्चों की शीघ्र पहचान, रेफरल तंत्र, कक्षा-स्तरीय रणनीतियाँ, ToFEI मैन्युअल एवं ड्रग-फ्री स्कूल दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन तथा "नशा मुक्त विद्यालय" पोर्टल पर स्व-घोषणा (Self-Declaration) की प्रक्रिया शामिल हो।	चरण-1: शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे— • नशीले पदार्थों के सेवन के जोखिम वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान। • रेफरल (Referral) व्यवस्था एवं प्रक्रिया। • मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से प्रभावित विद्यार्थियों के प्रबंधन हेतु कक्षा-स्तरीय रणनीतियाँ। • ToFEI मैन्युअल एवं ड्रग-फ्री स्कूल परामर्श (Advisory) का प्रभावी कार्यान्वयन। • "नशा मुक्त विद्यालय" पोर्टल पर स्व-घोषणा (Self-Declaration) हेतु चेकलिस्ट भरने की प्रक्रिया। चरण-2: शिक्षकों का क्षमता निर्माण (Capacity Building) किया जाएगा।	DoSEL/NCERT/ SCERTs एवं राज्य
6	विद्यालय परिसर के भीतर ToFEI (तंबाकू-मुक्त शैक्षणिक संस्थान) एवं मादक द्रव्यों के दुरुपयोग संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों के लिए एक समर्पित हैंडबुक / मार्गदर्शिका का विकास।	विद्यालय प्रधानाचार्यों एवं नोडल शिक्षकों के लिए एक कार्यान्वयन हैंडबुक/मार्गदर्शिका तैयार की जाएगी, जिससे वे तंबाकू एवं नशीले पदार्थों से संबंधित जागरूकता गतिविधियों का प्रभावी संचालन कर सकें। इसमें मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से प्रभावित विद्यार्थियों के प्रबंधन एवं कक्षा-कक्ष में आवश्यक कार्यवाही से संबंधित दिशा-निर्देश भी शामिल होंगे।	NCERT
7	सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण (बी.एड., डी.एल.एड.) में एक मॉड्यूल का समावेश तथा समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण में इसे शामिल करना।	एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जाएगा तथा इसे सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों (बी.एड., डी.एल.एड.) में शामिल किया जाएगा। साथ ही, समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के सेवाकालीन (In-service) प्रशिक्षण में भी इसे NCTE के सहयोग से सम्मिलित किया जाएगा।	DoSEL / NCTE / राज्य
8	NCERT द्वारा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू, मादक द्रव्यों एवं शराब के दुरुपयोग संबंधी सामग्री का अद्यतन (अपग्रेडेशन) तथा 'मनोदर्पण' पोर्टल की पहुँच का विस्तार।	DoSEL, NCB, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, NCERT तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों का एक कार्यदल (Working Group) गठित किया जाएगा। यह कार्यदल विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत तंबाकू, मादक द्रव्यों एवं शराब के दुरुपयोग से संबंधित वर्तमान IEC (सूचना, शिक्षा एवं संचार) सामग्री का अद्यतन करेगा, ताकि उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अधिक	DoSEL / NCERT

		प्रासांगिक बनाया जा सके।	
9	पीएम ई-विद्या टीवी चैनलों के माध्यम से 'परिचर्चा' सत्रों की निरंतरता बनाए रखना, जिनका मुख्य उद्देश्य जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन हो।	'परिचर्चा' सत्र छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को मनोसामाजिक (Psycho-social) सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण (Well-being) तथा समग्र विकास को बढ़ावा देना है। बच्चों में जागरूकता एवं सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए इन सत्रों का नियमित रूप से संचालन जारी रखा जाएगा।	NCERT – आयोजक सहभागिता: विद्यालय एवं स्कूल बोर्ड (राज्य, केंद्र एवं निजी)
10	MyGov प्लेटफॉर्म पर छात्रों एवं अभिभावकों को लक्षित करते हुए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना।	तबाकू एवं नशीले पदार्थों से संबंधित विषयों पर जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ एवं प्रतियोगिताएँ समय-समय पर MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएँगी।	DoSEL/NCERT एवं राज्य (States)
11	प्रतिवर्ष विश्व तबाकू निषेध दिवस (31 मई) एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस (26 जून) का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन।	प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में विश्व तबाकू निषेध दिवस (31 मई) तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस (26 जून) मनाया जाएगा। साथ ही 31 मई को विश्व तबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।	DoSEL, राज्य, NCERT, CBSE

कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा एवं-प्रमुख उपलब्धियाँ (2026–2029)

वर्ष	प्रमुख कार्यक्षेत्र (Focus Area)	मुख्य हितधारक (Key Stakeholders)	लक्ष्य (Milestone)
2026–27	पोटेल का शुभारंभ (IEC) सामग्री का विकास। पाठ्यक्रम को सुदृढ़ बनाना। शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं हैंडबुक का विकास। विद्यालयों को नशा मुक्त क्षेत्र-Drugs-Free Zones घोषित करना। समझौता ज्ञापन (MoU) को क्रियान्वित करना। जागरूकता अभियानों की शुरुआत। निगरानी एवं समय-समय पर समीक्षा।	क्रियान्वयन : DoSEL, NCERT, CBSE, निजी विद्यालय, स्कूल बोर्ड, NCTE, राज्य प्रदेश एवं विद्यालय। सहयोगी हितधारक : MoHFW, DoSJE, NCB तथा नागरिक समाज संगठन (CSOs) – IEC सामग्री, जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रमों के विकास में सहयोग।	40–50% विद्यालय ToFEI मानकों के अनुरूप नशा मुक्त किया जाना।
2027–28	शिक्षक प्रशिक्षण का बड़े पैमाने पर विस्तार (कस्केडिंग मोड में)। SCERT के माध्यम से IEC सामग्री का अनुवाद एवं स्थानीयकरण। विद्यालयों को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित करना। मनोदर्पण आउटरीच का विस्तार। संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय। मध्याविधि समीक्षा एवं दस्तावेजीकरण।	उपरोक्त सभी हितधारकों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वयन एवं सहयोग।	75% विद्यालय ToFEI मानकों के अनुरूप तथा नशा मुक्त।
2028–29	सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण क्रियान्वयन सेवा-पूर्व (Pre-service) एवं सेवाकालीन (On-the-job) प्रशिक्षण। व्यवहार परिवर्तन अभियानों को सतत रूप से चलाना। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सेवाओं से बेहतर समन्वय। नियमित समीक्षा एवं प्रलेखन।	सभी संबंधित विभाग, संस्थान एवं हितधारकों द्वारा पूर्ण कार्यान्वयन।	100% विद्यालय ToFEI मानकों के अनुरूप तथा पूर्णतः नशा-मुक्त।

निगरानी एवं समीक्षा तंत्र – विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग(DoSEL)

स्तर (Level)	निगरानी का माध्यम (Monitoring Instrument)	आवृत्ति (Frequency)
राष्ट्रीय स्तर (DoSEL)	DoSEL के सक्षम प्राधिकारी की अध्यक्षता में अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।	वर्ष में दो बार (अर्धवार्षिक)
DoSEL (प्रभाग स्तर)	डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित कर कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।	प्रत्येक तिमाही (त्रैमासिक)
राज्य स्तर	जिलों द्वारा अनुपालन का सत्यापन एवं रिपोर्टिंग की जाएगी।	मासिक / त्रैमासिक
जिला स्तर	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला NCORD समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा तथा उनके अनुपालन प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाएगी।	मासिक / त्रैमासिक

उच्च शिक्षा विभाग-

उच्च शिक्षा संस्थान (HELs), जो बड़ी और विविध युवा आबादी की जरूरतों का पूरा करते हैं, जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान करने और रोकथाम से पुनर्वास के निरंतर प्रयासों को मजबूत करने के लिए प्रथम-प्रतिक्रिया मंच के रूप में अपार क्षमता रखते हैं। इस संदर्भ में प्रस्तावित 03 वर्षीय कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण घटक समन्वित प्रयासों के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों को नशामुक्त बनाने पर केंद्रित है।

उपर्युक्त के आलोक में, यह निर्दिष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित विभागों को निम्नलिखित प्रमुख हस्तक्षेप को अपनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

1. निवारक शिक्षा (Preventive education)-

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए "मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार" पर 2-क्रेडिट मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन। विस्तृत दिशा निर्देश अलग से साझा किये जायेंगे।

2. क्रेडिट आधारित इंटरनशिप के अवसर (Credit-based Internship Opportunities)-

विशेष रूप से समाज कार्य और मनोविज्ञान के छात्रों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर इंटरनशिप की सुविधा प्रदान करना -

- DoSJE द्वारा समर्थित नशा मुक्ति केन्द्र।
- मेडिकल कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में नशा उपचार की सुविधाएं (ATFs) और नशा मुक्ति केन्द्र।
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम लगे गैर सरकारी संगठन (NGOs/VOs)
- राज्य औषधि मांग न्यूनीकरण सेल (State Drug Demand Reduction Cell)

3. नए छात्रों का संवेदीकरण (Sensitization of Freshers)-

नवागंतुक छात्रों के लिए एक सप्ताह के प्रेरण कार्यक्रम कि हिस्से के रूप में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम पर एक समर्पित सत्र को शामिल करना।

4. क्षमता निर्माण (Capacity Building)-

SWAYAM, मदन मोहन मालवीय, नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, और चेतना व्याख्यान श्रृंखला जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से पदार्थ उपयोग विकार पर संकाय सदस्यों परामर्श दाताओं और छात्रों का प्रशिक्षण।

5. जागरूकता सृजन और व्यवहार परिवर्तन संचार (Awareness Generation and Behavior Change Communication)-

- वार्षिक उत्सवों, युवा उत्सवों, खेल कार्यक्रमों, कुलपति सम्मेलनों और परिसर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियों का संचालन करना।
- NMBA शपथ का प्रचार

- प्रमुख संस्थागत कार्यक्रमों और राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय दिवसों के दौरान ऑफलाइन शपथ लेना।

- छात्रों और सकाय के बीच NMBA ई-शपथ पोर्टल का व्यापक प्रचार
 - c. 14446 हेल्पलाइन के संबंध में संवेदीकरण, जिसमें शामिल हैं -
 - परामर्श सहायता का प्राविधान
 - छात्रों और माता-पिता/अभिभावकों तक हेल्पलाइन जानकारी का प्रसार।
 - NMBA द्वारा समर्थित नशा मुक्ति केन्द्रों के बारे में जागरूकता।
 - d. संस्थागत चैनलों, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों और अन्य उपयुक्त प्लेटफार्मों के माध्यम से गतिविधियों का पर्याप्त मीडिया कवरेज सुनिश्चित करना।
- उक्त के अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थानों में-

1. NMBA जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करें, जैसे मैराथन, वॉकथान, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैलियां, युवा संवाद-कार्यशालाएं और संवादात्मक मंच।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों में परामर्श सेवाओं को स्थापित या सुदृढ़ करें।
3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन दिवसों के साथ NMBA प्राथमिकताओं को जोड़ें।
4. NCC/MY भारत स्वयं सेवकों के माध्यम से पड़ोस में संवेदीकरण अभियान चलाएं।
5. नशीली दवाओं की रोकथाम और स्वस्थ जीवनशैली पर फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन करें।
6. कल्याण और रोकथाम को बढ़ावा देने वाली नशा-विरोधी हॉस्टल समितियों की स्थापना करें।
7. संरचित गतिविधियों के साथ नशा मुक्त परिसर सप्ताह नामित करें।
8. ऑनलाइन अभियान, वेबिनार और सोशल मीडिया जुड़ाव पहल चलाएं। (जैसे नशा मुक्त विश्वविद्यालय)
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई भी अन्य गतिविधि।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग-

- a. वास्तविक समय डेटा संग्रह और निगरानी के लिए "MY BHARAT" पोर्टल के माध्यम से NMBA में युवाओं को मास्टर वालंटियर्स (नशा मुक्त मित्र) के रूप में जोड़ना सुनिश्चित करें।
- b. स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों सहित जमीनी स्तर पर मादक द्रव्यों के सेवन के संबंध में नियमित और व्यवस्थित जागरूकता का संवेदीकरण गतिविधियों के संचालन के लिए "MY BHARAT" और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों को व्यवस्थित रूप से लामबंद करना।
- c. सभी प्रासंगिक कार्यक्रमों, आयोजनों, पोर्टलों और IEC सामग्रियों में NMBA दृश्यता तत्वों का अनिवार्य एकीकरण-जिसमें लोगो, शुभंकर, हेल्पलाइन नम्बर (14446), और शपथ क्यूआर कोड शामिल हैं। कार्यक्रमों पोर्टलों और IEC सामग्रियों के बारे में जानकारी गूगल ड्राइव लिंक- <https://drive.google.com/drive/folders/1cArYFi8v9vyhU9Gd3UGodEYg8R1usp=drive>
- d. नशा मुक्ति और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के निवारण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन और समान समझ सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) के TAPAS प्लेटफार्म के माध्यम से सभी जिला युवा अधिकारियों का मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों पर समयबद्ध तरीके से अभिविन्यास और क्षमता निर्माण पूरा करना।
- e. मापने योग्य लक्ष्यों और परिणामों के साथ MY BHARAT की वार्षिक कार्य योजना के भीतर नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने की गतिविधियों का स्पष्ट समावेश।
- f. पर राष्ट्रीय तीन वर्षीय कार्य योजना के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

महिला एवं बाल विकास-

- a. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को NMBA के लिए "नशा मुक्त मित्र" (NMM) के रूप में पहचानने और उन्हें जोड़ने के लिए उचित निर्देश जारी करना।
- b. यह सुनिश्चित करना कि NMBA लोगो (NMBA LOGO), NMBA शुभंकर, और नशामुक्ति

हेल्पलाइन नम्बर 14446 का उपयोग करते हुए मौजूदा जागरूकता अभियानों में "नशा मुक्त मित्र" को एकीकृत किया जाय।

- c. इन "नशा मुक्त मित्र" और अन्य हितधारकों की सहायता से जमीनी स्तर पर नशीली दवाओं के खिलाफ सामूहिक शपथ (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना। ऑनलाइन शपथ के लिए क्यूआर कोड, NMBA लोगो और NMBA शुभंकर इस लिंक पर संलग्न

हैं- <https://drive.google.com/drive/folders/1cArYFi8v9vyhU9Gd3UGodEYg8RWeusp=sharing>

भवदीय

Digitally signed by
ANURAG YADAV

Date: 21-07-2026

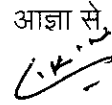
17: (अनुराग यादव)

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जिलाधिकारी, को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-9 के पत्रदिनांक 14.07.2026 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से


(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव

**Government of India
Ministry of Home Affairs
Narcotics Control Bureau
R.K. Puram, New Delhi – 110066**

F No. III/1/22/NCORD/9th Apex /2025/Pt.-2(3)

Date: 14/05/2026

To,

The Directors General of Police,
All States and Union Territories.

Sub: UHM directions of the 9th Apex Level NCORD Committee Meeting-reg.

Sir/Madam,

Kindly refer to the above cited subject.

2. In this context, as a follow-up to the directions issued by the Hon'ble Union Home Minister during the 9th Apex Level NCORD Committee Meeting held on 09.01.2026, a DO letter dated 20.03.2026 (Copy enclosed) was jointly issued under the signature of the Union Home Secretary and Secretary, Department of School Education & Literacy to all States/UTs for strengthening preventive and awareness measures relating to Drug Demand Reduction. The major action points highlighted in the aforesaid communication are summarized below:

- a) Launch of "Nasha Mukta Vidyalaya" Portal for monitoring Tobacco-Free Educational Institutions (ToFEI) and Drug-Free compliance in schools across the country.
- b) Declaration of a 500-meter radius around schools/educational institutions as "Drug-Free Zone" with mandatory signage and reporting mechanism for violations.
- c) Integration of age-appropriate substance abuse prevention modules in NCERT, CBSE and State Board curriculum under Life Skills and Health Education.
- d) Development of standardized IEC material including posters, handbooks, documentaries and awareness content for students, teachers and parents in regional languages.
- e) Teacher Training & Capacity Building through dedicated modules on early identification, counselling, referral mechanisms and implementation of Drug-Free School guidelines.
- f) Inclusion of drug awareness and prevention modules in B.Ed., D.El.Ed. and annual in-service teacher training programmes.
- g) Strengthening of Manodarpan and School Health Programme with focus on tobacco, alcohol and substance abuse prevention.
- h) Conduct of nationwide awareness campaigns through MyGov, PM e-Vidya/ Paricharcha and observance of World No Tobacco Day and International Day Against Drug Abuse.
- i) Achievement of phased targets up to 2029:

- 2026-27: 40-50% schools ToFEI compliant & Drug-Free
- 2027-28: 75% compliance
- 2028-29: 100% ToFEI compliant & Drug-Free schools

j) **Monitoring** through digital dashboards, quarterly reviews, State-level verification and District NCORD Committee reviews.

3. Further, a **DO letter dated 22.04.2026 (copy enclosed)** was issued jointly by the Union Home Secretary and Secretary, Department of Social Justice & Empowerment to all States/UTs for strengthening monitoring and coordination of Drug Demand Reduction initiatives under the NCORD framework. The key points emphasized in the aforesaid communication are as under:

- a) All State and District NCORD meetings should invariably include a **dedicated agenda** item on Drug Demand Reduction activities, including Nasha Mukh Bharat Abhiyan (NMBA).
- b) **Officers associated** with implementation of National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) and NMBA should be encouraged to participate in such meetings.
- c) **Regular monitoring and review** of progress of Drug Demand Reduction activities should be undertaken during these meetings.
- d) **Minutes** of such meetings should be **uploaded on the NCORD Portal**.

4. It is requested that recommendations made in aforesaid communication may please be utilized for proper coordination and implementation in your States/UTs for achieving the objective of Drug Free India.

Your sincerely

Encl: As above.

VV 19/5/26.
(Anurag Garg)

Director General

Cc:

1. The Heads of ANTFs of all States/UTs – For kind information please.
2. The JS (IS-II), MHA, New Delhi – For kind perusal & Info that access to the NCORD Portal has been provided on the email ID: js-is2@mha.gov.in, and also to the DS & SO concerned in IS-II Division.
3. The JS (SD), MoSJE, New Delhi – For kind perusal & info that access to the NCORD Portal has been provided on the email ID: jssd-msje@nic.in.
4. All Dy. Directors General (Regions)/Zonal Directors – for information and necessary coordination please.

No. 11485/MS/SECY GI/2026

ACS (Sec. Edu./Social Welfare)/4185

ACS (Home/Health)

Govind Mohan
Home Secretary
Ministry of Home
Affairs,
Government of India
E-mail- hshso@nic.in
Tel. 24010001



सत्यमेव जयते

Sanjay Kumar
Secretary,

Department of School
Education & Literacy,
Government of India

E-mail- secy.sel@nic.in
Tel. 24015101

(संयुक्त सचिव
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन)

D.O. No. 28-1/2026-PACE-Part(1)

20th March, 2026

सचिव (M)

Dear Chief Secretary,

24/3/26
(संयुक्त सचिव
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन)

Substance abuse among children and youth has emerged as a serious public health and social concern in the country, necessitating coordinated and sustained interventions. As per the report "Magnitude of Substance Use in India (2019)" conducted by AIIMS in collaboration with the Ministry of Social Justice & Empowerment, a significant proportion of substance users belong to the adolescent and young age group. Further, the Global Youth Tobacco Survey (GYTS-4) indicates that around 8.5% of school students in the age group of 13-15 years are using tobacco in some form, which often acts as a gateway to other forms of substance abuse. These findings underline the urgent need for early preventive interventions through the school education system.

2. The rising incidence of substance abuse was deliberated at the 9th Apex Meeting of Narco-Coordination Centre (NCORD) held under the Chair of Hon. Union Home Minister Shri. Amit Shah, wherein it was emphasized that in the fight against drugs, all departments of the Government of India should prepare a roadmap upto 2029 and establish a time-bound review mechanism for its implementation. He emphasized that the health of the youth, their ability to think and perform, and the growing discontent in society are all linked to this problem. It was announced that beginning from March 31, 2026, all stakeholder Departments will together launch a three-year collective campaign against this problem, in which the working methodology of all pillars against drug abuse will be defined, targets will be set, and time-bound reviews will be conducted. The 9th Apex meeting of NCORD has therefore decided that over the next three years, all stakeholders involved have to fight on all fronts against drugs across the country and make India a "Drug-Free India", and make every effort to protect the country's youth from drugs.

3. In pursuance of the above directions, a comprehensive and structured three-year Action Plan under the *Nasha Mukta Bharat Abhiyan* has been developed for implementation in the educational institutions and is being shared with all States and Union Territories (copy enclosed) for adoption in mission mode. The Action Plan, Inter

alia, incorporates provisions for declaring the area within a 500-metre radius of schools as drug free zones and mandates reporting of any violations by the Head of School/Nodal Teacher to the concerned local authorities, including the police, for appropriate action. The Action Plan adopts a holistic and convergent approach, encompassing sustained awareness and sensitization programmes, integration of preventive education within the school environment, capacity building of teachers and school heads, active engagement of students through peer-led initiatives, and the use of IEC interventions such as posters, signage boards for drugs free area and creative campaigns. It also envisages strengthened linkages with health systems, counselling support and local administration, supported by a clearly defined monitoring and reporting framework at school, district and state levels.

4. In view of the above, it is imperative that the States/UTs accord the highest priority to the implementation of the 3 year Action Plan. It is therefore, requested that the Action Plan is disseminated to all schools including private schools without delay and implemented in a time bound and result-oriented manner. The States/UTs may also designate dedicated State and District Nodal Officers for effective coordination and establish a robust mechanism for periodic monitoring and review of progress, with due convergence across relevant departments and agencies such as Police / Narcotics Law Enforcement Agencies/local administration etc. by timely reporting.

5. Given the seriousness of the issue, It is expected that the implementation of this initiative will be closely supervised at the appropriate level so as to ensure meaningful outcomes on the ground and States/UTs are requested to furnish an Action Taken Report to the concerned Department in a timely manner. The collective and sustained efforts of all stakeholders will be critical in creating a safe, healthy and substance-free environment for our children.

6. We look forward to your continued support and cooperation in this important national endeavour.



(Govind Mohan)

With regards,



(Sanjay Kumar)

Encl: as above

The Chief Secretaries of all States/UTs.

Nasha Mukh Bharat Abhiyan

(Implementation of 3 years Action Plan for making Educational Institutions Nasha Mukh Bharat by March 2029)



Department of School Education & Literacy
Ministry of Education
Govt. of India

3-Year Action Plan for States/UTs & ABs- D/o School Education & Literacy

Sr. No.	What to Do?	How to Do?	Who will Do?
1	Launch of a dedicated "Nasha Mukh Vidyalaya" portal for schools declaring themselves tobacco and drugs free.	A portal "Nasha Mukh Vidyalaya" to be launched by DoSEL for monitoring Implementation of Drug Free Zone (DFZ) compliance in schools. Schools registered under UDISE+, government/govt-aided & private management, will report compliance.	DoSEL /States/UTs/ Schools
2	A 500-meter radius around all educational institutions shall be declared a "Drug-Free Zone".	As per the direction issued in the 9 th Apex NCORD meeting, the 500-meter radius around educational institutions shall be declared as "Drugs Free Zone". A signage board on the entrance/outside of the school shall be mandatorily placed conveying that selling/consumption of any kinds of drugs is prohibited within the radius of 500 meter. In case of violation, the same shall be reported to the police/Narcotic Law Enforcement Agencies.	Schools/ Local Police /District Narcotics Law Enforcement Agencies/Local administration
3	Integration of age-appropriate curriculum on substance abuse prevention into Life Skills/ Health Education.	Already embedded in the NCERT curriculum from the Middle Stage onwards and in the CBSE Life Skills curriculum across all schooling levels. Now, State Boards will also be requested to ensure its integration through adaptation or adoption.	DoSEL / NCERT/ States/UTs

3-Year Action Plan for States/UTs & ABs- D/o School Education & Literacy

Sl. No.	What will be done?	Who will do?
1	Development of a standardized IEC material on tobacco, drugs and substance abuse.	DoSEU/ NCERT/ States/UTs/ SCERTs
2	Development of a training module for teachers on early identification, referral mechanisms, classroom strategies and implementation of ToFEI manual and drugs free schools including self-declaration of Nasha Mukti Vidyalaya portal.	DoSEU/ NCERT/ SCERTs & States/UTs

3-Year Action Plan for States/UTs & ABs- D/o School Education & Literacy

Sl. No.	What will be done?	Who will do?
1	Development of a dedicated Teachers Handbook/ Guide for effective implementation of ToFEI, substance abuse guidelines within school premises.	NCERT
2	Inclusion of a module in pre-service teacher training (B.Ed., D.El.Ed.) including on the job annual training of teachers under Samagra Shiksha.	DoSEU/ NCTE/ States/UTs
3	Upgradation of the contents on tobacco, substance abuse and alcohol abuse in the School Health Programme by NCERT and widen the reach of Manodarpan portal.	DoSEU/ NCERT

3-Year Action Plan for States/UTs & ABs- D/o School Education & Literacy

Sr. No.	What to Do?	How to Do?	Who will Do?
9	Continuation of Paricharcha sessions through PM e-Vidya TV channels focusing on awareness and behavioural change	Paricharcha sessions are designed to provide psycho-social support to students, teachers, and parents across India, focusing on mental health, well-being, and holistic development. These sessions shall be continued for awareness and behavioural change in the children.	NCERT – organizer & Participation by Schools/School Boards (State, Centre & Private)
10	Periodic awareness campaigns on MyGov platform targeting students and parents.	Awareness and Sensitization activities/competition focused on the themes related to tobacco and drugs shall be organised on MyGov platform time to time.	DoSEL/NCERT States/UTs
11	Annual nationwide observance of World No Tobacco Day (31 st May) and International Day against Drug Abuse (26 th June)	Observance of World No Tobacco Day (31 May), and International Day against Drug Abuse (26 th June) every year in schools and national level program on 31 st May for World No Tobacco Day.	DoSEL/ States/UTs/ NCERT/ CBSE

Timeline & Milestones (2026–2029) for implementation of Action Plan

Year	Focus Area	Key Stakeholders	Milestone
2026-27	Portal launch; development of IEC materials; curriculum strengthening; teacher training module & handbook development; declaration of schools as Drugs-Free Zones; operationalization of MoU; Initiation of awareness campaigns; monitoring and periodic review.	Implementation by DoSEL through NCERT, CBSE/Pvt School Boards/ NCTE/ States/UTs/Schools	40 to 50% schools ToFEI compliant & Drugs Free
2027-28	Scale-up of teacher training (cascading mode); translation & contextualization of IEC through SCERTs; declaration of schools as Drugs-Free Zones; expansion of Manodarpan outreach; convergence with line Ministries; mid-term & periodic review/ documentation.	Stakeholder Support in developing IEC, Sensitization sessions: MoHFW, DoSJE, NCB & CMI Society Organizations (CSOs)	75% schools ToFEI compliant & Drugs Free
2028-29	Full implementation across States/UTs; pre-service & on the job training; sustained behaviour change campaigns; strengthened rehabilitation linkages; periodic review/documentation.		100% ToFEI compliance & Drugs Free

Monitoring & Review Mechanism- D/o School Education & Literacy

Level	Monitoring Instrument	Frequency
National (DoSEL)	Bi-annual review chaired by Competent Authority (DoSEL)	Twice yearly
DoSEL (Division Level)	Digital dashboard & quarterly review meetings with States/UTs on the implementation	Quarterly
State Level	District compliance verification & reporting	Monthly/Quarterly
District Level	DM level district NCORD Committee Review meeting, field verification by visiting schools and review their compliance report.	Monthly/Quarterly



THANK YOU!

Sopa9m: Joint DO letter dt. 20.03.2026 reg. Three Year Action Plan under Nasha Mukh Bharat Abhiyan developed for implementation in Educational Institutions.

< pace.dosel@gmail.com >

Mon, 23 Mar 2026 6:14:11 PM +0530

To "cs-andaman"<cs-andaman@nic.in>,"cs-andamannicobar"<cs-andamannicobar@gov.in>,"cs-arunachal"<cs-arunachal@nic.in>,"chiefsecretary-ap"<chiefsecretary-ap@ap.gov.in>,"cs"<cs@ap.gov.in>,"cs-assam"<cs-assam@nic.in>,"cs-bihar"<cs-bihar@nic.in>,"adviser-chd"<adviser-chd@nic.in>,"csoffice.cg"<csoffice.cg@gov.in>,"secy-edu-dd"<secy-edu-dd@nic.in>,"csdelhi"<csdelhi@nic.in>,"cs-goa"<cs-goa@nic.in>,"chiefsecretary"<chiefsecretary@gujarat.gov.in>,"secedu-pri"<secedu-pri@gujarat.gov.in>,"spd-gcse"<spd-gcse@gujarat.gov.in>,"cs"<cs@hry.nic.in>,"cs-hp"<cs-hp@nic.in>,"cs-jharkhand"<cs-jharkhand@nic.in>,"cs"<cs@karnataka.gov.in>,"chiefsecy"<chiefsecy@kerala.gov.in>,"util2"<util2@util.gov.in>,"pstocomsecutl"<pstocomsecutl@gmail.com>,"pry.sec"<pry.sec@ladakh.gov.in>,"chiefsecretary"<chiefsecretary@ladakh.gov.in>,"cs"<cs@mp.nic.in>,"secy.sed"<secy.sed@mp.gov.in>,"director-rsk"<director-rsk@mp.gov.in>,"cs"<cs@maharashtra.gov.in>,"cso-meg"<cso-meg@nic.in>,"cs-manipur"<cs-manipur@nic.in>,"cs-manipur"<cs-manipur@gov.in>,"cs-mizoram"<cs-mizoram@nic.in>,"csnld"<csnld@nic.in>,"csori"<csori@nic.in>,"cs"<cs@py.gov>,"cs.pon"<cs.pon@nic.in>,"cs"<cs@punjab.gov.in>,"cs"<cs@punjabmail.gov.in>,"pant"<pant@ias.nic.in>,"csraj"<csraj@rajasthan.gov.in>,"cm-skm"<cm-skm@nic.in>,"cs"<cs@tn.gov.in>,"cs"<cs@telangana.gov.in>,"cs.tripura"<cs.tripura@nic.in>,"csup"<csup@nic.in>,"cs-uttarakhand"<cs-uttarakhand@nic.in>,"chiefsecyuk"<chiefsecyuk@gmail.com>,"cs-westbengal"<cs-westbengal@nic.in>,"dulooa"<dulooa@ias.nic.in>,"cs-jandk"<cs-jandk@nic.in>

Cc "hshso@nic.in"<hshso@nic.in>,"secy.sel"<secy.sel@nic.in>,"A Srija"<srija.a@gov.in>,"M L Meena Dir (PACE)"<ml.meena29@gov.in>,"Ram Singh Jt. Dir."<singh.ram92@gov.in>,"Abdul Momin"<abdulmomin7272@gmail.com>,"Vivek Tiwari"<vivekthwari069@gmail.com>

Tags  Not in Contacts

Respected Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the DO letter dt: 20.03.2026 on the subject cited above for your kind information and necessary action.

--
With Regards,

Policy Analysis and Community Engagement (PACE) Section, EA Bureau,
Dept. of SE&L, Ministry of Education,
Shastri Bhawan, New Delhi

2 Attachment(s)

D.O. letter dt. 20.03.2026.pdf
885.3 KB

Three Year Action Plan DoSEL...
111.8 KB

Govind Mohan
Home Secretary
Ministry of Home
Affairs



Sudhansh Pant
Secretary
Department of Social
Justice and
Empowerment

D.O.No. 12-1/2020-DP-II

April 22, 2026

Dear Chief Secretary,

I would like to draw your attention to the fact that the alarming rise in substance abuse was extensively deliberated in the 9th Apex meeting of the Narco Coordination Centre (NCORD) held under the chairmanship of the Hon'ble Union Home Minister. The meeting emphasized that all Ministries and Departments of the Government of India must prepare a comprehensive roadmap up to 2029, backed by a strong time-bound monitoring and review mechanism. It was decided that, all stakeholder Departments will jointly launch a three-year nationwide campaign against drug abuse. Under this campaign, the operational framework for each pillar of the anti-drug strategy will be clearly defined, specific and measurable targets will be set, and regular reviews will be conducted to ensure accountability.

2. In pursuance of these decisions, the 9th Apex meeting of NCORD resolved that all stakeholders shall wage a vigorous and multi-pronged battle against drugs across the country during the next three years with the firm objective of building a 'Drug-Free India' and protecting the country's youth from the harmful effects of substance use. In furtherance of the above, a detailed and structured three-year Action Plan under the Nasha Mukh Bharat Abhiyan (NMBA) has been formulated for implementation across various settings with the support of multiple stakeholders. The Action Plan is to be executed in mission mode.

3. In order to ensure focused attention on both supply reduction and demand reduction aspects, it has been decided that from the next NCORD meeting onwards at all levels^o (National, State, and District), apart from discussions on drug supply reduction, dedicated time shall be allocated for reviewing Drug Demand Reduction activities, including the implementation of the Nasha Mukh Bharat Abhiyan (NMBA) and the National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR).

4. Accordingly, you are requested to kindly ensure that:

- a. The meeting schedule of all NCORD meetings at the State and District levels includes a specific and dedicated slot for discussion on Drug Demand Reduction activities, including Nasha Mukh Bharat Abhiyan.
- b. Officers concerned with the implementation of the National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) and Nasha Mukh Bharat Abhiyan (NMBA) are invariably invited to participate in these meetings.
- c. Regular monitoring and review of the progress of demand reduction activities, including NMBA, are taken up in these dedicated sessions.
- d. Minutes of the said meetings be circulated among all stakeholders including Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Home Affairs.

5. Your personal attention and proactive intervention in this matter will be crucial for the successful implementation of the decisions taken in the 9th Apex NCORD meeting and for achieving the objective of a Drug-Free India.

6. We look forward to your continued support and cooperation in this important national endeavour.

With kind regards,

Yours sincerely,


(Sudhansh Pant)


(Govind Mohan)

To,
Chief Secretaries of all States/UTs

CC:

1. ACS/Principal Secretaries/Secretaries (Social Welfare Department)
2. ACS/Principal Secretaries/Secretaries (Home Department)